भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 216

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशाखापत्तनम में बड़े उद्योग

***216. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन बड़े और मेगा उद्योगों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों की कुल कितना निवेश किए जाने की प्रतिबद्धता थी और अब तक वास्तव में कितना निवेश प्राप्त हुआ है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के आंकड़ों सहित इन उद्योगों द्वारा कितने रोजगार सृजित किए गए;

(घ) इन उद्योगों की वर्तमान प्रचालन स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई उद्योग प्रचालनरत नहीं है या बंद हो गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र में इन उद्योगों के कार्यकरण को सहायता देने और बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : आंध्र प्रदेश सरकार के प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाले बड़े और मेगा उद्योगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें उनके क्षेत्र, किए गए निवेश, सृजित रोजगार और प्रचालनरत होने संबंधी विवरण शामिल है:

कंपनी का नाम	**निवेश का प्रकार (नया/विस्तार)**	**उद्योग का प्रकार (क्षेत्र)**	**कार्यकलाप का प्रकार**	**निवेश (करोड़ रूपए में)**	**प्रत्यक्ष रोजगार**	**उत्पादन शुरू करने का महीना और वर्ष**	**अप्रत्यक्ष रोजगार**	**प्रचालन की स्थिति**
डिविस लैबोरेट्रीज़ लि., ईओयू - इकाई	नया	बल्क ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स	बल्क ड्रग्स	740.96	820	मार्च, 2020	624	कार्यशील

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

(च) : उद्योग मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक पहलें और नीतियां तैयार करती है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की जारी स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वि भिन्न कदम उठाए हैं। सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस/एमआईआईयूएस) आदि जो देशभर में प्रमुख अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाती हैं। इसके साथ ही, निवेश में तेजी लाने के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ (पीडीसी) का गठन किया गया है।

****